SAFALTA CLASS™

An Initiative by अमर उजाला

INDIAN

POLITY

BY – SUJEET BAJPAI SIR

Union and its Territory

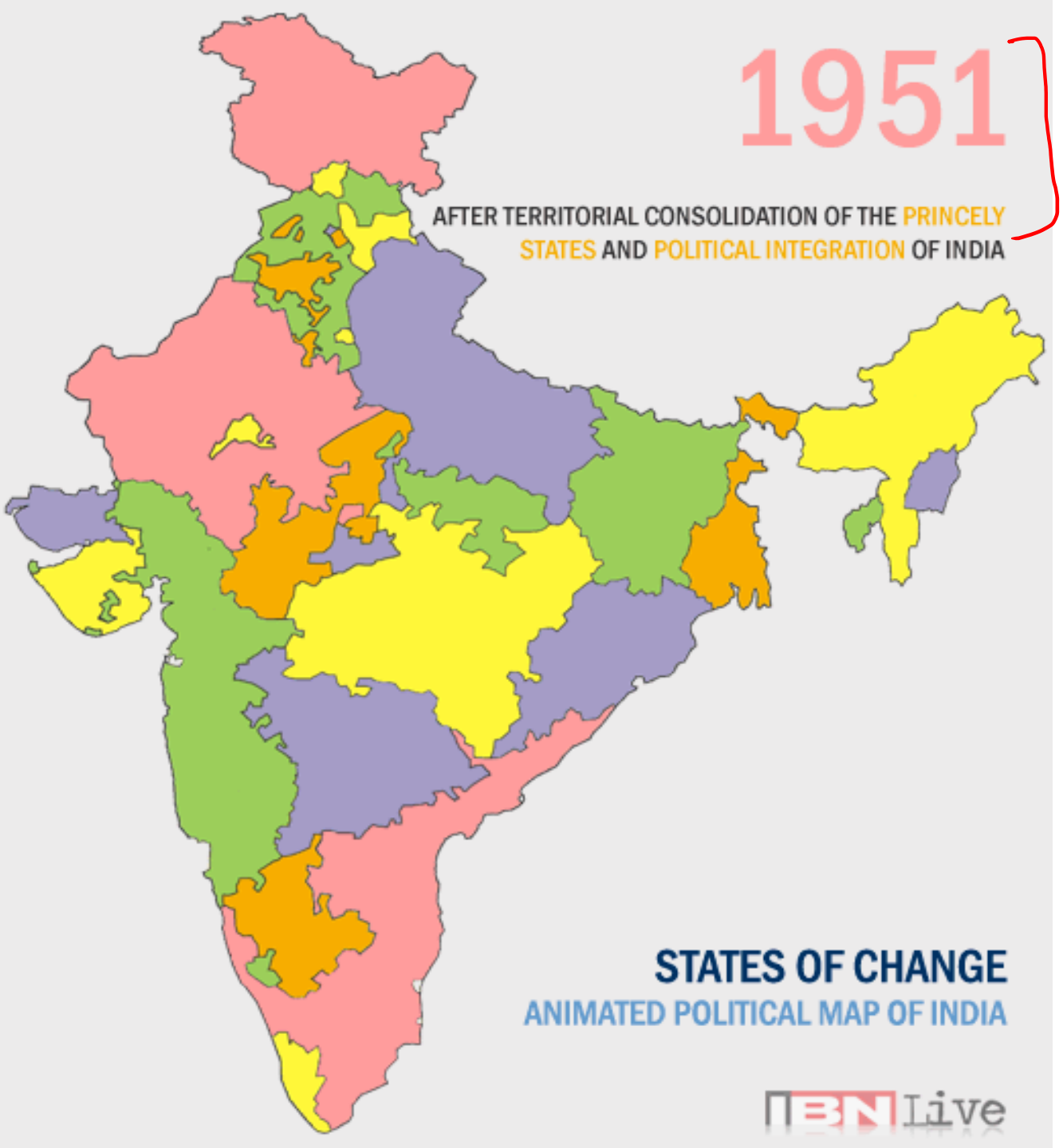

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

1947

1926

According to Article 1, the territory of India can be classified into three categories:

India that is Bharat shall be union of states.

1. **Territories of the states**
2. **Union territories**
3. **Territories that may be acquired by the Government of India at any time.**

अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत के क्षेत्र को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. राज्यों के प्रदेशों
2. केंद्र शासित प्रदेश
3. ऐसे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत किए जा सकते हैं।

Article 2 grants two powers to the Parliament:

(a) the power to admit into the Union of India new states; and

(b) the power to establish new states.

अनुच्छेद 2 संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है:

(क) भारत के नए राज्यों के संघ में प्रवेश करने की शक्ति; और

(ख) नए राज्यों की स्थापना की शक्ति ।

The first refers to the admission of states which are already in existence while the second refers to the establishment of states which were not in existence before.

पहला उन राज्यों के प्रवेश को संदर्भित करता है जो पहले से अस्तित्व में हैं जबकि दूसरा उन राज्यों की स्थापना को संदर्भित करता है जो पहले अस्तित्व में नहीं थे ।

Article 3, on the other hand, relates to the formation of or changes in the existing states of the Union of India.

In other words, Article 3 deals with the internal re-adjustment of the territories of the constituent states of the Union of India.

दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारत संघ के मौजूदा राज्यों के गठन या बदलाव से संबंधित है।

दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 3 भारत संघ के घटक राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुन समायोजन से संबंधित है ।

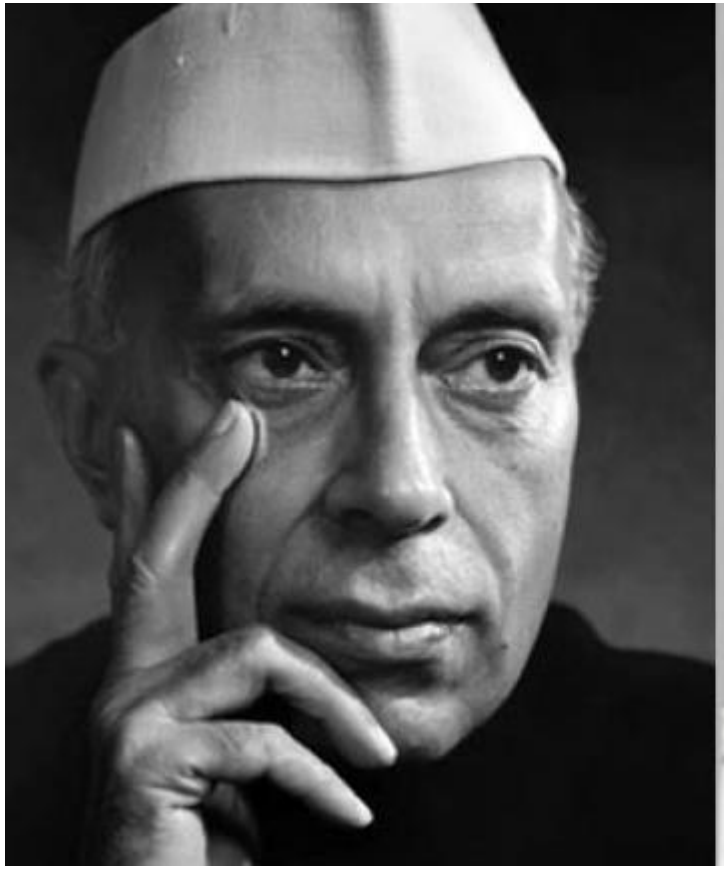

J

V

Pattabhi

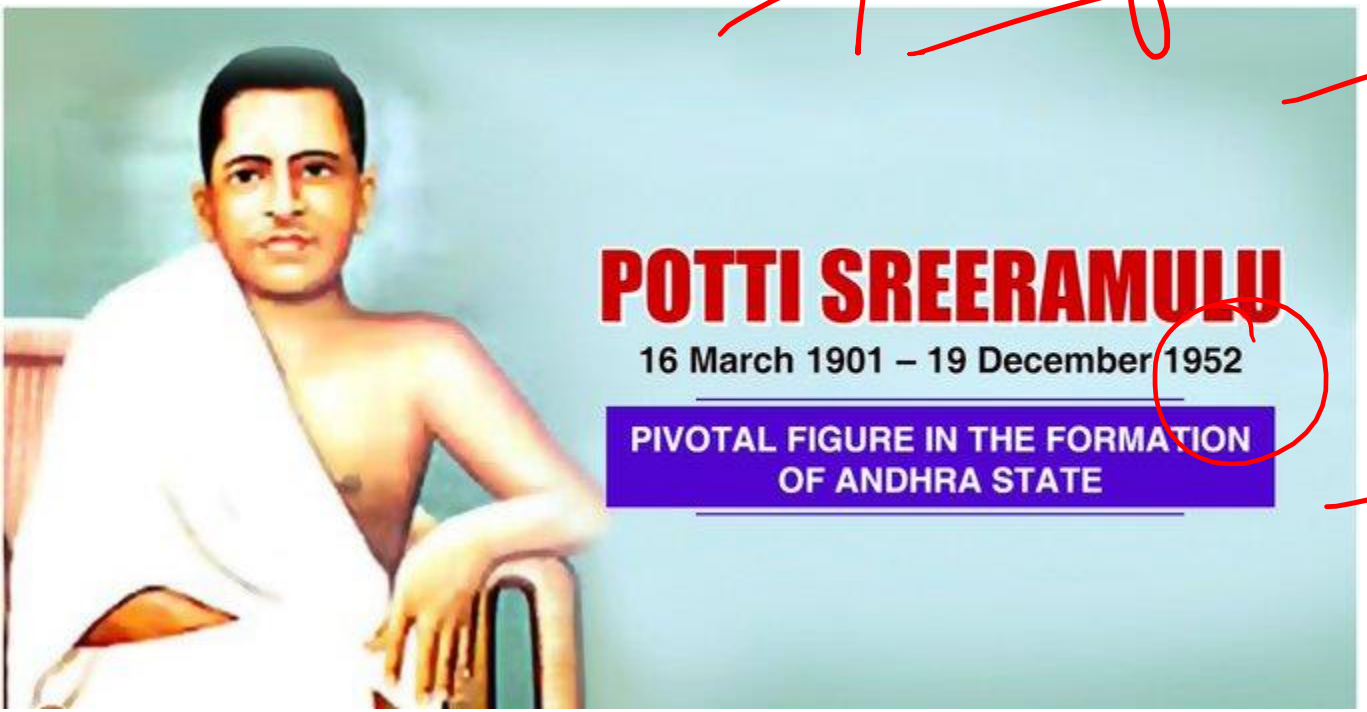

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

Congress

Gandhian leader

Madras

Telgu

Tamil

Andhra

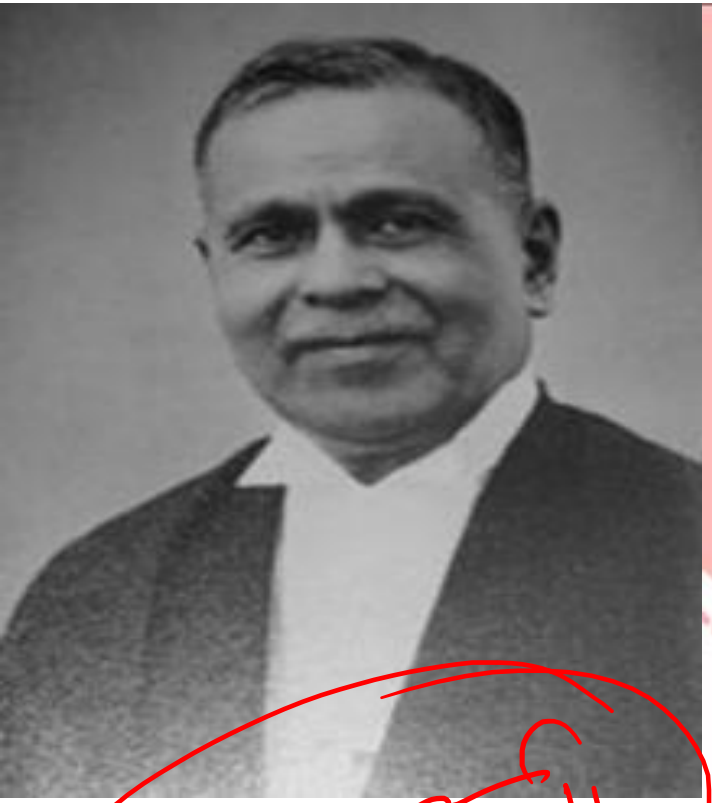

फजल अली
(1)

H.N. कुंजरू
(2)

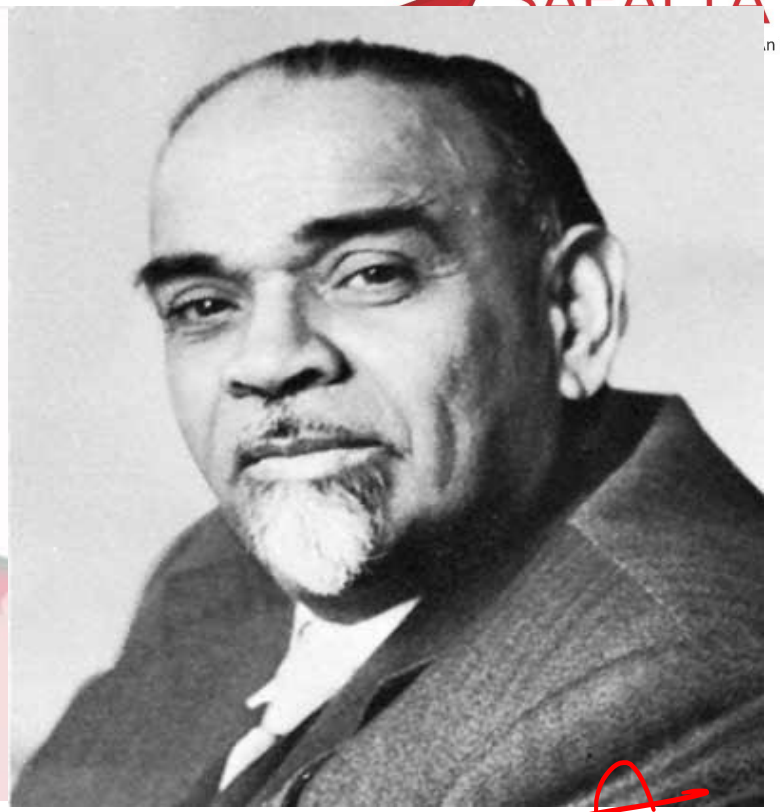

K.M. पणिक्कर
(3)

Dhar Commission and JVP Committee:

The integration of princely states with the rest of India has purely an ad hoc arrangement. There has been a demand from different regions, particularly South India, for reorganisation of states on linguistic basis.

धर आयोग और जेवीपी समिति:

शेष भारत के साथ रियासतों के एकीकरण में विशुद्ध रूप से तदर्थ व्यवस्था है ।

भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण भारत से मांग की गई है।

Accordingly, in June 1948, the Government of India appointed the Linguistic Provinces Commission under the chairmanship of S K Dhar to examine the feasibility of this.

The commission submitted its report in December 1948 and recommended the reorganisation of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor.

तदनुसार, जून 1948 में भारत सरकार ने इसकी व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की।

आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और भाषाई फैक्टर के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की।

This created much resentment and led to the appointment of another Linguistic Provinces Committee by the Congress in December 1948 itself to examine the whole question afresh.

इससे काफी नाराजगी पैदा हुई और दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस द्वारा एक और भाषाई प्रांत समिति की नियुक्ति कर इस पूरे सवाल की नए सिरे से जांच की गई।

It consisted of Jawaharlal Nehru, Vallahbhai Patel and Pattabhi Sitaramayya and hence, was popularly known as JVP Committee.

It submitted its report in April 1949 and formally rejected language as the basis for reorganisation of states.

इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लाहभाई पटेल और पट्टाभि सीतारामैया शामिल थे और इसलिए उन्हें जेवीपी कमेटी के नाम से जाना जाता था ।

इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और औपचारिक रूप से भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में अस्वीकार कर दिया ।

However, in October 1953, the Government of India was forced to create the first linguistic state, known as Andhra state, by separating the Telugu speaking areas from the Madras state.

This followed a prolonged popular agitation and the death of Potti Sriramulu, a Congress person of standing, after a 56-day hunger strike for the cause.

हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र राज्य के नाम से जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इसके बाद लंबे समय तक लोकप्रिय आंदोलन चला और कांग्रेस के खड़े व्यक्ति पोट्टी श्रीरामुलु की मौत के बाद 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इस कारण से मौत हो गई ।

Fazl Ali Commission

The creation of Andhra state intensified the demand from other regions for creation of states on linguistic basis.

This forced the Government of India to appoint (in December 1953) a three-member States Reorganisation Commission under the chairmanship of Fazl Ali to re-examine the whole question.

फजल अली आयोग

आंध्र राज्य के निर्माण से भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए अन्य क्षेत्रों से मांग तेज हो गई।

इससे भारत सरकार को (दिसंबर 1953 में) फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने को मजबूर होना पड़ा और पूरे सवाल की फिर से जांच की गई।

Its other two members were K M Panikkar and H N Kunzru.

It submitted its report in September 1955 and broadly accepted language as the basis of reorganisation of states. But, it rejected the theory of 'one language–one state'.

(State Reorg. Act → 1956)

Its view was that the unity of India should be regarded as the primary consideration in any redrawing of the country's political units.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

इसके अन्य दो सदस्य केएम पाणिकर और एच एन कुंजरू थे।

इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में मोटे तौर पर भाषा को स्वीकार किया।

लेकिन, इसने 'एक भाषा-एक राज्य' के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका विचार यह था कि देश की राजनीतिक इकाइयों को फिर से तैयार करने में भारत की एकता को प्राथमिक विचार माना जाना चाहिए।

Source: USA

Part-3 (Art-12-35)

→ FR
Art-14-32

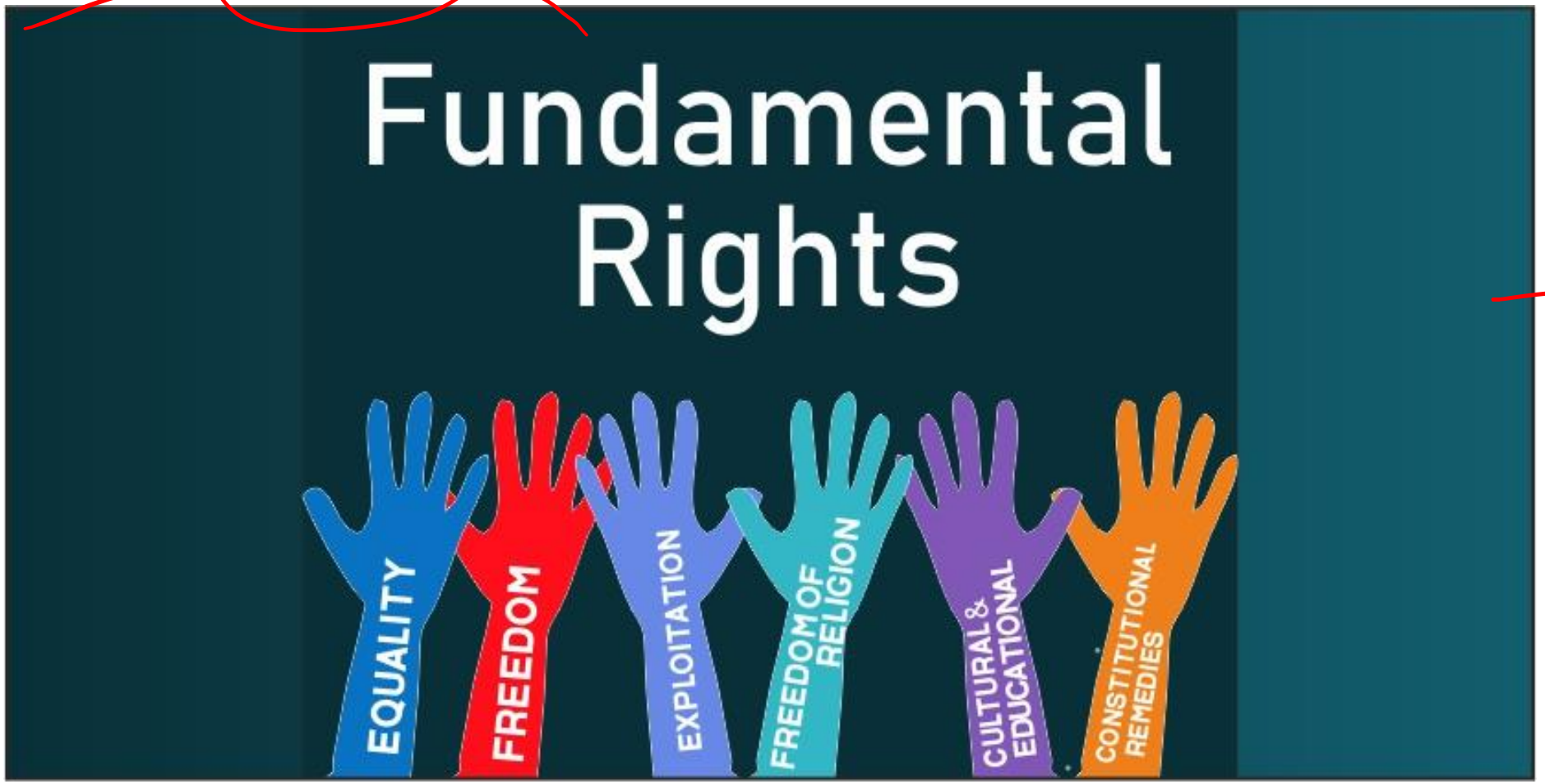

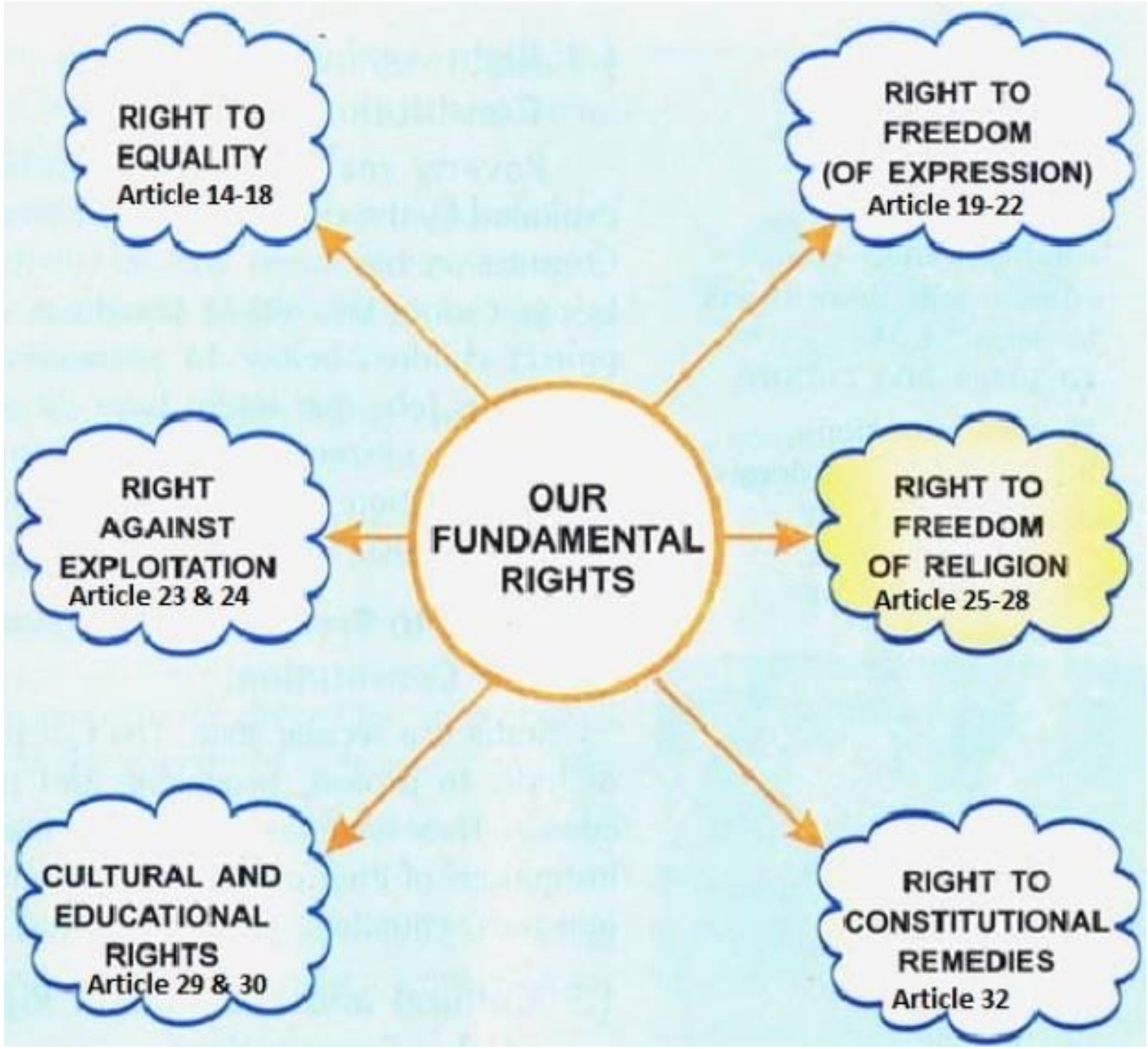

Why term "Fundamental"
मूलभूत
⇓
Very essential for dev. of Human.

The Fundamental Rights are enshrined in Part III of the Constitution from Articles 12 to 35.

In this regard, the framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of USA (i.e., Bill of Rights).

मौलिक अधिकार संविधान के भाग-III में अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रतिष्ठापित हैं ।

इस संबंध में संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (यानी अधिकारों के विधेयक) से प्रेरणा प्राप्त की।

Originally, the Constitution provided for seven Fundamental Rights-

1. Right to equality (Articles 14–18)
2. Right to freedom (Articles 19–22)
3. Right against exploitation (Articles 23–24)

Present
6

मूल रूप से संविधान में सात मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था-

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
3. शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

4. Right to freedom of religion (Articles 25–28)
5. Cultural and educational rights (Articles 29–30)
6. Right to property (Article 31)
7. Right to constitutional remedies (Article 32)

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
6. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)
7. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

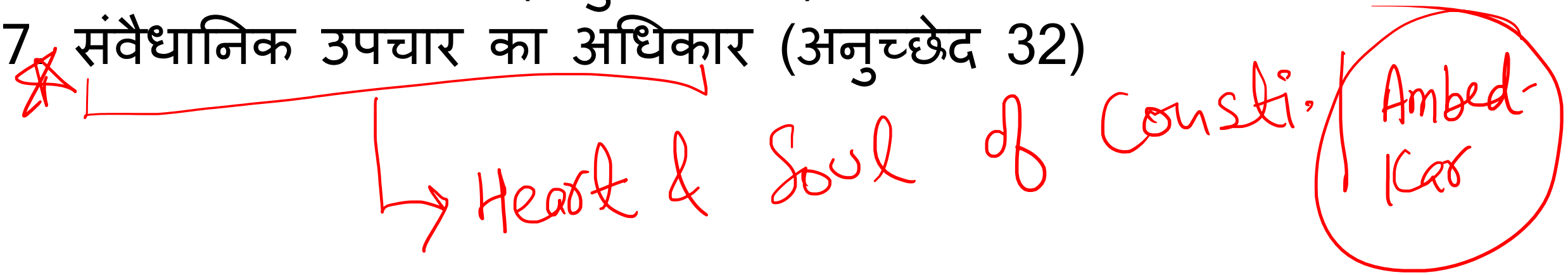

However, the right to property was deleted from the list of Fundamental Rights by the 44th Amendment Act, 1978.

It is made a legal right under Article 300-A in Part XII of the Constitution. So at present, there are only six Fundamental Rights.

हालांकि, 44 वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।

इसे संविधान के भाग 12वीं में अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसलिए वर्तमान में केवल छह मौलिक अधिकार हैं ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Features of Fundamental Rights:

1. Some of them are available only to the citizens.
2. They are not absolute but qualified. The state can impose reasonable restrictions on them.

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं:

1. उनमें से कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।
2. वे निरपेक्ष नहीं बल्कि निर्बंधन के अधीन हैं। राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

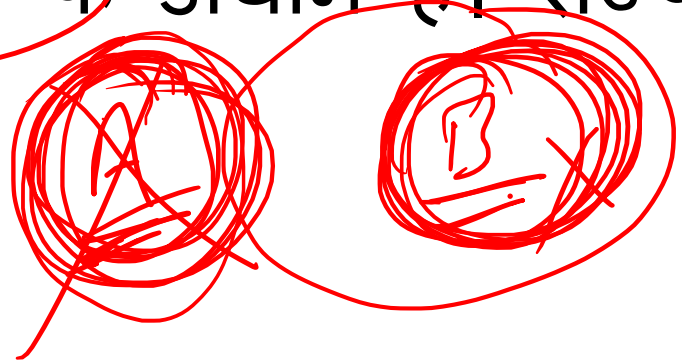

3. They are justiciable, allowing persons to move the courts for their enforcement, if and when they are violated.

4. They are defended and guaranteed by the Supreme Court.

3. वे **Justiciable** हैं, व्यक्तियों को उनके प्रवर्तन के लिए अदालतों में स्थानांतरित करने की अनुमति है, अगर और जब वे उल्लंघन कर रहे हैं ।

4. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका बचाव और गारंटी दी जाती है ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

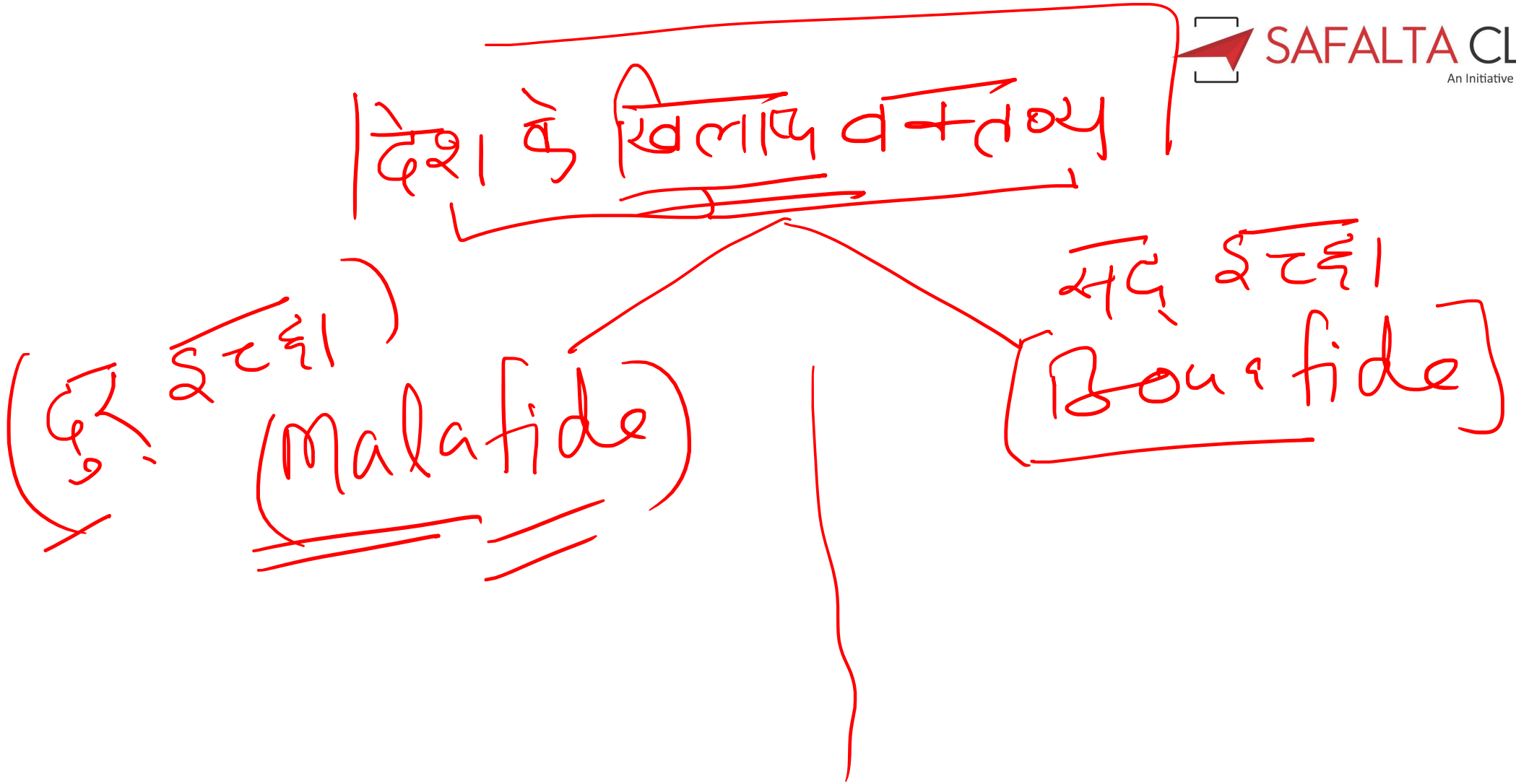

5. They can be suspended during the operation of a National Emergency except the rights guaranteed by Articles 20 and 21.

5. वे अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटी अधिकारों को छोड़कर एक राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है ।

6. Their application to the members of armed forces, para-military forces, police forces, intelligence agencies and analogous services can be restricted or abrogated by the Parliament (Article 33).

6. सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अनुरूप सेवाओं के सदस्यों को उनके आवेदन को संसद (अनुच्छेद 33) द्वारा प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है ।

7. Fundamental rights can be restricted while martial law is in force in any area.

Martial law means 'military rule' imposed under abnormal circumstances to restore order (Article 34).

7. मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है जब मार्शल लॉ किसी भी क्षेत्र में लागू है।

मार्शल लॉ का मतलब है ' सैन्य शासन ' (अनुच्छेद 34)।

Category	Consists of
1. Right to equality (Articles 14–18)	(a) Equality before law and equal protection of laws (Article 14). (b) Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth (Article 15). (c) Equality of opportunity in matters of public employment (Article 16). (d) Abolition of untouchability and prohibition of its practice (Article 17). (e) Abolition of titles except military and academic (Article 18).

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Equality =>
समानता

समता / Equity =>

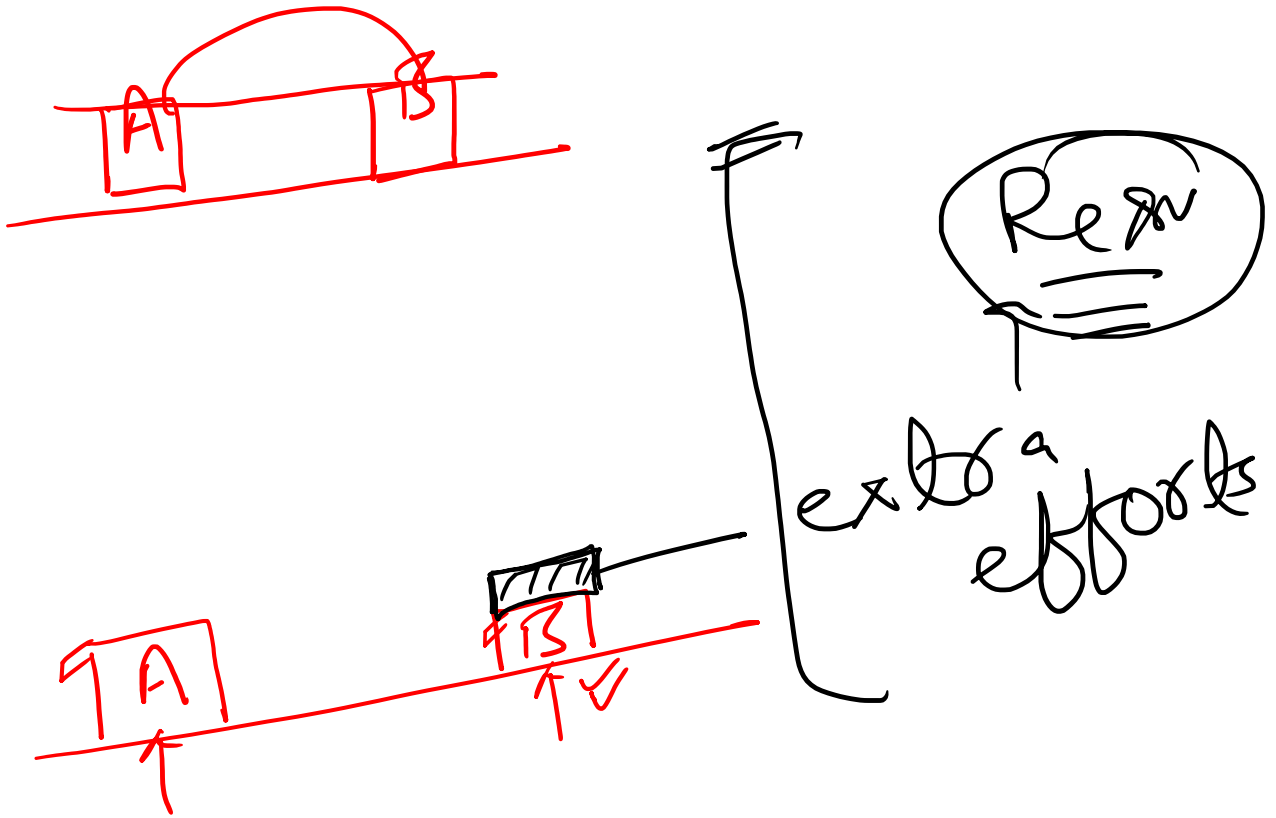

2. Right to freedom (Articles 19–22)

(a) Protection of six rights regarding freedom of: (i) speech and expression, (ii) assembly, (iii) association, (iv) movement, (v) residence, and (vi) profession (Article 19).

(b) Protection in respect of conviction for offences (Article 20).

(c) Protection of life and personal liberty (Article 21).

(d) Right to elementary education (Article 21A).

(e) Protection against arrest and detention in certain cases (Article 22).

Rt. to Internet + Rt. to Privacy

3. Right against exploitation (Articles 23–24)	(a) Prohibition of traffic in human beings and forced labour (Article 23). (b) Prohibition of employment of children in factories, etc. (Article 24).

4. Right to freedom of religion (Article 25–28)

(a) Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion (Article 25).

(b) Freedom to manage religious affairs (Article 26).

(c) Freedom from payment of taxes for promotion of any religion (Article 27).

(d) Freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institutions (Article 28).

[Rt. to Convert] X

5. Cultural and educational rights (Articles 29–30)	(a) Protection of language, script and culture of minorities (Article 29). (b) Right of minorities to establish and administer educational institutions (Article 30).

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

(a) विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)।

(b) धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)।

(c) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)।

(d) अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध (अनुच्छेद 17)।

(e) सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाए सभी उपाधियों पर रोक (अनुच्छेद 18)

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

(a) छह अधिकारों की सुरक्षा (I) वाक् एवं अभिव्यक्ति, (II) सम्मेलन, (III) संघ, (IV) संचरण, (V) निवास, (VI) वृत्ति (अनुच्छेद 19)।

(b) अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)।

(c) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)।

(d) प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21)।

(e) कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22)।

SS™ रउजाला

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

(a) बलात् श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23)।

(b) कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)	(a) अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)।
	(b) धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)।
	(c) किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)।

	(d) कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)।
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)	(a) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा (अनुच्छेद 29)। (b) शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (अनुच्छेद 30)।
6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)	मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें शामिल याचिकाएं हैं-(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण, (ii) परमादेश, (iii) प्रतिषेध, (iv) उत्प्रेषण, (v) अधिकार पृच्छा (अनुच्छेद 32)।